

### जानवरों का शिकार

1403. श्री रामदेव भड़ारी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जुलाई, 1996 के "नवभारत टाइम्स" में "अमीरों का मनोरंजन, जानवरों का सफाया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो इस समाचार का अंगूष्ठ क्या है; और

(ख) सरकार, हस्तिनापुर बन्यजीव विहार में शिकारियों द्वारा मारे जा रहे बन्य-जन्तुओं की सुरक्षा हेतु क्या कार्रवाई कर रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य पंत्री (फैटन जय नारायण प्रसाद निवाद): (क) जी, हां। यह खबर उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर अभ्यारण्य की सीमा, इसकी कम्पनी अवस्थिति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के निष्कर्षों, प्रधावी व्यक्तियों द्वारा अवैध शिकार की समस्या, झाबर मृग सहित बन्यजीव-जन्तुओं को बिजली का करंट लगा कर, मारने, भूमि के अवैध कट्टने, घास और मछली का अवैध नीलाम तथा अभ्यारण्य के प्रबंधन के लिए अपर्याप्त और असुरक्षित फील्ड स्टाफ के बारे में है।

(ख) मुख्य बन्यजीव वार्डन ने खबर दी है कि फील्ड स्टाफ द्वारा नियमित रूप से गत लगाती जा रही है और अवैध शिकार को रोकने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं जिसे 1995-96 में काफी हद तक नियंत्रित किया गया है।

अभ्यारण्य के वास्तविक और तथा की गई कार्रवाई में है:—

हस्तिनापुर अभ्यारण्य में उत्तर प्रदेश के भेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद और बिजनौर जिलों का 2073 वर्ग किमी<sup>2</sup> का क्षेत्र आता है। इसका 186.26 वर्ग किमी<sup>2</sup> क्षेत्र ही गज्ज वन और बन्यजीव विभाग के नियंत्रणाधीन है और शेष वनेतर क्षेत्र है जिसमें काफी लोगों की आबादी और खेती है। गज्ज मुख्य बन्यजीव वार्डन ने खबर दी है कि सिंचाई विभाग के द्वारा क्षेत्र जो अभ्यारण्य का हिस्सा है, में स्थानीय पंचायत द्वारा मछलियों, घास आदि की नीलामी की जाती है जिसके लिए गज्ज मुख्य बन्यजीव वार्डन ने आपत्ति की है। अपर्याप्त और असुरक्षित फील्ड स्टाफ के साथ-साथ ये मसले अभ्यारण्य के वनेतर भूमि में

बन्यजीव-जन्तुओं की सुरक्षा के लिए समस्या बन रहे हैं। मुख्य बन्यजीव वार्डन ने यह भी खबर दी है कि 1995-96 के दौरान अपराध के 62 मामलों का पता लगाया गया जिनमें से 9 मामले न्यायालयों को भेजे गए। केवल 2 मामले ही बन्यजीव-जन्तुओं के अवैध शिकार किए जाने से संबंधित हैं और झाबर मृग के अवैध शिकार की कोई खबर नहीं है।

### Rise in Subsidy of Chemical Fertilizers

1404. SHRI PARAG CHALIHA:  
SHRI GOVINDRAM MIRI:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what will be the total increase per annum due to recent rise in subsidy rates on chemical fertilizers; and

(b) what is the justification, if any, of this rise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SHEES RAM OLA): (a) On account of increase in the rates of special concession on decontrolled phosphatic and potassic fertilizers, the provision of Rs. 500 crore made in the interim budget for 1996-97 has been revised to Rs. 2224 crores.

(b) The rates of special concession have been enhanced with a view to making these fertilizers available to farmers at reasonable prices so as to increase their consumption and improve the N.P.K. ratio.

राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव

1405. श्री राधाकिशन मालवीय: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993—96 के दौरान राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अन्तर्गत सरकार को कितने राज्यों से कौन-कौन सी नदियों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) योजनाओं के नाम तथा उनमें से प्रत्येक के लिए आवंटित धनराशि के संबंध में व्यौग क्या है;